यू.एस.-ईरान के बीच तनावपूर्ण संबंध

लेखक - मोहम्मद अयूब (सेवानिवृत्त प्रोफेसर, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) से संबंधित है।

द हिन्दू

13 सितम्बर, 2019

"जॉन बोल्टन को बाहर निकालना और वाशिंगटन पर इजराइल का कम प्रभाव, तनाव में संभावित कमी का संकेत देता है।"

अगर यह अफगानिस्तान नहीं है तो ईरान होना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को एक रणनीतिकार के रूप में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए 2020 के चुनावों से पहले एक आकस्मिक विदेश नीति सफलता की सख्त आवश्यकता है, जो अमेरिकी विदेश नीति के संदर्भों को एक नया रूप दे सके। किम जोंग उनके साथ उनके सौहार्दपूर्ण व्यवहार ने उत्तर कोरिया के परमाणु शस्त्रागार या उसके बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर किसी भी प्रकार का अंकुश लगाने में सफलता प्राप्त नहीं कर सकी है।

ट्रम्प द्वारा तालिबान को युद्धविराम स्वीकार कराने की कोशिश की गई ताकि वह अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों को वापस लेना शुरू कर सकें और 2016 के चुनाव प्रचार के दौरान इन्होंने जो वादा किया था उसे पूरा किया जा सके, लेकिन काबुल के विरोध और सैन्य कार्रवाई को रोकने के लिए तालिबान की अनिच्छा के कारण अभी तक यह रुका पड़ा है। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि श्री ट्रम्प के पास अपनी कूटनीतिक निपुणता का प्रदर्शन करने का एकमात्र क्षेत्र ईरान ही बच गया है।

श्री ट्रम्प के कुछ करीबी सहयोगी, विशेष रूप से हाल ही में बर्खास्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन एक नीति को बढ़ावा दे रहे हैं, जो ईरान में शासन परिवर्तन की वकालत करती है, चाहे वो बल द्वारा ही क्यों न हो। हालाँकि, श्री ट्रम्प ईरान के साथ एक खुले युद्ध में अमेरिका का नेतृत्व नहीं करना चाहते हैं। यह रुख बड़े पैमाने पर अमेरिकी सैनिकों को घर वापस लाने के उनके अभियान के वादे के प्रति लगाव से प्रेरित है जिसके कारण उन्हें पिछले चुनाव में भारी संख्या में वोट प्राप्त हुए थे। इसलिए वे अपने सैनिकों को अस्थिर पश्चिम एशिया में भेजने के विचार की कड़ी निंदा करते हैं।

जरीफ की बिआरित्ज की यात्रा

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन के साथ वार्ता के लिए ईरानी विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ की बिआरित्ज की एक अनिर्धारित यात्रा के बाद ये प्रवृत्ति फ्रांस में हाल ही में संपन्न जी7 बैठक में प्रदर्शित हो गयी थी। राष्ट्रपति मैक्रोन ने घोषणा की कि ट्रम्प-रूहानी की बैठक 'आने वाले हफ्तों' में होने की संभावना है।

श्री ट्रम्प ने कहा कि उनका ईरान पर शासन बदलने का कोई इरादा नहीं था और उन्होंने घोषणा की कि सही परिस्थितियों में, वह निश्चित रूप से श्री रूहानी के साथ बैठक करेंगे।

अपने भाषण में, श्री रूहानी ने भी यह संकेत दिया था कि वह ट्रम्प के साथ बात करने के लिए तैयार हैं लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि वह श्री ट्रम्प से तब ही मिलेंगे जब वाशिंगटन 2018 में परमाणु समझौते से ट्रम्प के बाहर निकलने के बाद तेहरान पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटा ले। इसके बाद, श्री ट्रम्प ने यह कहकर पलटवार किया कि उन्हें राष्ट्रपति रूहानी से मिलने में कोई समस्या नहीं है।

इजराइल और जॉन बोल्टन दोनों अमेरिका और ईरान के बीच संभावित तालमेल के प्रस्तावक के रूप में सबसे बड़ी बाधा हैं। श्री ट्रम्प, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ अपने घनिष्ठ संबंध के बावजूद, यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इजराइल के नेता अमेरिका पर बहुत अधिक निर्भर हैं और विशेष रूप से श्री ट्रम्प पर ताकि इस तरह बैठक को अवरुद्ध किया जा सके। श्री नेतन्याहू

इस सप्ताह इस समझ की पुष्टि करते दिखे, जब उन्होंने कहा जाहिर है, मैं अमेरिकी राष्ट्रपति को नहीं बताऊंगा कि कब मिलना है या किसके साथ मिलना है।

इजराइल के साथ मतभेद

बहरहाल, अमेरिका और ईरान द्वारा अपने संबंधित मुद्दों को बेहतर करने के इस संबंध ने इजराइल को चिंता में डाल दिया है। यही कारण है कि देर से ही श्री नेतन्याहू एक बार फिर ईरान के परमाणु हथियारों की क्षमता के बारे में शोर कर रहे हैं। यहां तक कि वह इस्फहान के पास एक परमाणु सुविधा की पहचान करने के लिए भी गए थे, उनके अनुसार जब उन्होंने इस जानकारी को सार्वजनिक किया तो ईरानियों ने उस स्थान के अस्तित्व को नष्ट कर दिया। हालांकि, इसके जवाब में ईरानी विदेश मंत्री जबाद जरीफ ने तुरंत इसका खंडन किया। यह स्पष्ट है कि ईरान के संबंध में अमेरिका और इजराल के उद्देश्यों के बीच एक बुनियादी असंगति व्याप्त है।

श्री बोल्टन ने ईरान के लिए हमेशा कठोर रुख अपनाएं रखा है और वे ईरान के संबंध में ट्रम्प प्रशासन द्वारा अपनाएं गए कई कठोर उपायों के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार भी हैं। ये जलमय खलीलजाद (एक अफगान-अमेरिकी राजनयिक) के एक सौदे के भी प्रबल विरोधी थे जिसमें अफगानिस्तान से अमेरिकी बलों की क्रमिक वापसी की बात शामिल थी। श्री बोल्टन ईरान के पूर्ण संप्रदायिकरण और शासन परिवर्तन से कम किसी भी सौदे के विरोध में रहते थे और इस वजह से ही श्री ट्रम्प नाराज थे, क्योंकि यह विदेशी सैन्य संघर्षों में शामिल होने की दिशा में किया जा रहा प्रयास था।

हालांकि, जॉन बोल्टन को हटाया जाना और ईरान के प्रति अमेरिकी नीति पर इजरायल के प्रभाव को कम करना, यह संकेत देता है कि वाशिंगटन तेहरान के साथ तनाव कम करने में रुचि रखता है। 10 सितंबर को विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ के बयान से इस बात की पुष्टि होती है कि इसकी संभावना बहुत है कि श्री ट्रम्प और श्री रूहानी के बीच एक बैठक इस महीने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के दौरान हो। इस तरह की बैठक, भले ही यह सभी विवादास्पद द्विपक्षीय मुद्दों को तुरंत हल नहीं कर सकती है, लेकिन एक बेहतर शुरुआत जरूर होगी, जो दीर्घकालिक रूप से वाशिंगटन और तेहरान दोनों को लाभान्वित करेगी।

GS World टीम...

अमेरिका और ईरान के बीच वे घटनाएं, जिसने विवाद को बढ़ाया

चर्चा में क्यों?

- अमेरिका और ईरान के रिश्ते हमेशा से तल्ख रहे हैं, लेकिन इन दिनों तनाव इतना बढ़ गया है कि दोनों युद्ध के मुंहाने पर खड़े हैं। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे के राजदूत बनकर तेहरान जाने की कवायद भी फेल हो चुकी है।
- ईरान द्वारा अमेरिकी ड्रोन मार गिराने के बाद अमेरिका हमला करने जा रहा था कि अंतिम समय में खुद को रोका। चिंगारी सुलग उठी है। वैश्विक मामलों पर गहरी नजर रखने वालों की मानें तो कभी भी यह ज्वालामुखी के धधक उठने का सबब बन सकती है।

1. परमाणु करार तोड़ ट्रंप ने की शुरुआत

- अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के समय ईरान और अमेरिका के बीच की गई परमाणु समझौते को डोनाल्ड ट्रंप ने आठ मई, 2018 को तोड़ दिया। ऐसा कर उन्होंने अपने चुनावी वायदे को पूरा भी किया। इस कदम ने दुनिया के ताकतवर देशों के बीच एक तनाव पैदा करने का काम किया।
- हालांकि, अमेरिका के डील से हटने के बाद भी फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, रूस, चीन और ईरान ने इस करार से बंधे रहने का फैसला किया था।

2. ईरान पर प्रतिबंधों के साथ बढ़ा तनाव

- ईरान की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने के उद्देश्य से सात अगस्त, 2018 को अमेरिकी प्रशासन ने वे सभी प्रतिबंध फिर से उस पर लगा दिए जिन्हें परमाणु करार के तहत हटा लिया गया था।
- इसके बाद से ही अमेरिका और ईरान में तनातनी बनी हुई है। ईरान ने कहा है कि वह अमेरिका की ओर से आने वाले हर खतरे का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है।

3. आइजीआरसी आतंकी संगठन घोषित, तल्खी और बढ़ी

- अमेरिका ने आठ अप्रैल, 2019 को ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आइजीआरसी) को आतंकी संगठन

घोषित किया।

- यह पहली बार था जब किसी दूसरे देश के सरकारी सुरक्षा एजेंसी के साथ ऐसा किया गया हो। बदले में ईरान ने भी अमेरिकी सेना को आतंकी समूह की संज्ञा दी। इससे तल्खी और बढ़ी।

4. तेल टैंकरों पर हमले ने किया आग में घी का काम

- तेल व्यापार के सबसे अहम जलमार्ग होरमूज की खाड़ी में 13 मई, 2019 को चार अमेरिकी तेल टैंकरों पर हमला किया गया।
- अमेरिका के सुरक्षा सलाहकार बॉलटन ने इसके लिए ईरान को दोषी बताया लेकिन ईरान ने आरोपों को खारिज कर दिया।
- इसके बाद 24 मई को अमेरिकी प्रशासन ने इस क्षेत्र में अपनी स्थिति और मजबूत करने के उद्देश्य से 1500 और सैनिकों को भेजने का फैसला किया।

5. ईरान ने ड्रोन मार गिराया

- ईरान ने 20 जून को अमेरिका का ड्रोन मार गिराया। दोनों देशों ने इस बात की पुष्टि तो की लेकिन अमेरिका का कहना था कि जब अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा पर उनका ड्रोन था, तब उसे गिराया गया जबकि ईरान ने दलील दी कि उसकी वायु सीमा में प्रवेश करने पर ही ड्रोन को निशाना बनाया गया।
- ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अब्बास मौसवी ने कहा है कि हम अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। अमेरिका चाहे कोई भी फैसले करे लेकिन ईरान अपनी सीमाओं का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं करेगा। हम हर खतरे का जवाब देने को तैयार हैं।

6. ईरान का जवाबी हमला होगा घातक

- अमेरिका को यह इल्म है कि अगर वह ईरान पर हमला करता है तो ईरान का जवाबी हमला कितना घातक होगा।
- ईरान इस बार अमेरिका को जवाब देने के साथ ही उसके यूएई जैसे मित्र देशों को भी निशाना बना सकता है। वह यह जोखिम नहीं उठा सकते।

7. ट्रंप के एजेंडे में अभी 2020 का चुनाव

- ट्रंप के एजेंडे में अभी 2020 का चुनाव है। वे एक और टर्म चाहते हैं। उन्होंने चुनाव के दौरान किए वादे निभाए हैं। चाहें परमाणु करार तोड़ना हो और आर्थिक प्रतिबंधों से ईरान की कमर तोड़नी हो।
- अब ऐसे में वह युद्ध कर खाड़ी क्षेत्र में कोई अस्थिरता पैदा करना नहीं चाहते। युद्ध से हमलावर देश की अर्थव्यवस्था, स्थिरता और विकास की गति भी बाधित होती है। वह ऐसा कर कोई जोखिम मोल नहीं लेना चाहते।

GS World
Committed To Excellence

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. **ईरान परमाणु समझौता से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-**

   1. अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन, फ्रांस और जर्मनी के साथ 2015 के समझौते में ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम पर लगाम लगाने की सहमति व्यक्त की थी।
   2. अमेरिका इस समझौते से बाहर हो रहा है क्योंकि उसका कहना है यह समझौता त्रुटिपूर्ण है और ईरान को अरबों डॉलर तक पहुँच प्रदान करता है।
   3. ईरान समझौता अपनी कमियों के बावजूद विश्व शक्तियों के एक साथ आने और एक जटिल मुद्दे को कूटनीतिक रूप से हल करने की क्षमता का अच्छा उदाहरण हो सकता था।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन असत्य नहीं है/हैं?

   (a) 1 और 2 (b) 1 और 3
   (c) 2 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

Expected Questions (Prelims Exams)

1. **Consider the following statements related to the Iran nuclear deal:**

   1. In the 2015 agreements with America, Britain, Russia, France and Germany, Iran agreed to regulate its nuclear program.
   2. The US is pulling out of this agreement because it says that the agreement is defective and gives Iran access to billions of dollars.
   3. The Iran agreement, despite its shortcomings, could have been a good example of the ability of world powers to come together and resolve a complex issue diplomatically.

   Which of the above statements are not correct?

   (a) 1 and 2 (b) 1 and 3
   (c) 2 and 3 (d) All of the above

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न: अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प के लिए अफगानिस्तान, उत्तर कोरिया के असफल प्रयोग के बाद ईरान के साथ विवाद सुलझाने का बेहतर अवसर है।' आपके अनुसार अमेरिका के लिए ईरान से संबंध सुधारना कितना महत्त्वपूर्ण है? अमेरिका-ईरान संबंध के वैश्विक निहितार्थों की भी चर्चा कीजिए। (250 शब्द)

Q. There is a better opportunity for US President Trump to resolve the dispute with Iran after the unsuccess with Afghanistan, North Korea. How important do you think America is to improve relations with Iran? Also discuss the global implications of the US-Iran relationship. (250 Words)

नोट : 12 सितंबर को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1 (d) होगा।